

पटसन सामग्री में अनविर्य पैकगि के लयि मानदंडों का वसितार

चरचा में कयों?

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पटसन वर्ष 2017-18 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक) के लयि खाद्यान्नों तथा चीनी की पैकगि हेतु अनविर्य रूप से पटसन सामग्री का प्रयोग कयि जाने के संबंध में सवीकृता प्रदान की गई है। इस नरिणय के प्रभावस्वरूप न केवल पटसन क्षेत्र की मांग में वृद्धि होगी, बल्कि इससे इस क्षेत्र पर नरिभर कामगारों तथा कसानों के जीविकोपार्जन में भी बढ़ोतरी होगी।

वशिषताएँ

- समिति द्वारा पटसन पैकगि सामग्री (Jute Packaging Material) अधनियम, 1987 के अंतर्गत अनविर्य पैकगि मानदंडों का वसितार कयि गया है।
- समिति के नरिणयों में यह व्यवस्था की गई है कि 90 प्रतिशत खाद्यान्न तथा 20 प्रतिशत चीनी उत्पादों की पैकगि अनविर्य रूप से पटसन की बोरीयों में की जाएगी।
- इस नरिणय के अंतर्गत यह भी आदेश दयि गया है कि पहली बार में खाद्यान्नों की पैकगि की पूरी खेप पटसन की बोरीयों के लयि प्रदान की जाएगी।

प्रभाव

- इस नरिणय से देश के पूरवी तथा पूरवोत्तर क्षेत्रों वशिषकर पश्चिमि बंगाल, बहिर, ओडशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रपुरा में रहने वाले कसान तथा कामगार लाभान्वति होंगे।

पटसन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लयि सरकार द्वारा कयि गए उपाय

- पटसन उद्योग मुख्यतः सरकारी क्षेत्र पर नरिभर उद्योग है, जो प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए से अधिक के पटसन उत्पादों की खरीद करता है।
- लगभग 3.7 लाख कामगार तथा लगभग 40 लाख कसान अपनी जीविका के लयि पटसन क्षेत्रों पर नरिभर हैं। इस दृष्टिकोण से सरकार पटसन क्षेत्र के विकास के लयि कच्चे पटसन की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में वृद्धि, पटसन क्षेत्र के वविधिकरण तथा पटसन उत्पादों को बढ़ाने और उनकी मांग को बनाए रखने के लयि प्रयास करती है।
- सरकार द्वारा इस संबंध में नमिनलखिति प्रयास कयि गए हैं-
 - ⇒ पटसन क्षेत्र में मांग की अभिवृद्धि के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी, 2017 से बांग्लादेश तथा नेपाल से पटसन के सामान के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (Definitive Anti Dumping Duty) लगाई गई है।
 - ⇒ इन उपायों के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश की 13 ट्वनि मल्लिों द्वारा पुनः प्रचालन आरंभ कयि गया, जिससे 20 हजार कामगार लाभान्वति हुए।
 - ⇒ इसके अलावा, एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने से भारतीय पटसन उद्योग के लयि स्वदेशी बाजार में 2 लाख एमटी पटसन सामानों की अतिरिक्त मांग की संभावना भी व्यक्त की गई है।
 - ⇒ पटसन आई-केयर (Jute ICARE) नामक व्यवस्था से कच्ची पटसन की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने हेतु भारत सरकार द्वारा बीज ड्रलि का प्रयोग करके लाइन में बुवाई, पहयि वाली कुदाल आदि के वतिरण की दशा में कार्य कयि जा रहा है।
 - ⇒ इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा नोकदार नरिई-उपकरण का प्रयोग करके वीड मैनेजमेंट, गुणवत्ता वाले प्रमाणति बीजों का वतिरण तथा माइक्रोबॉयल समर्थति रेटगि प्रदान करने जैसी कृषि संबंधी प्रक्रयिओं का प्रसार करने की दशा में भी कार्य कयि जा रहा है। इन सभी कार्यों और प्रयासों का उद्देश्य पटसन की मांग में वृद्धि करके पटसन कसानों को सहायता पहुँचाना है।

वर्तमान स्थिति

- इन सभी व्यवस्थाओं से कच्चे पटसन की गुणवत्ता और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- इतना ही नहीं पटसन कसानों की आय में 10 हजार रुपए प्रति हैकटेयर तक की वृद्धि हुई है।
- पटसन कसानों की मदद के उद्देश्य से भारतीय पटसन नगिम (Jute Corporation of India - JCI) को वर्ष 2014-15 से प्रारंभ 4 वर्ष के लयि 204 करोड़ रुपए का अनुदान दयि गया, ताकि पटसन क्षेत्र में मूलय स्थिरिकरण सुनिश्चित कयि जा सके।
- पटसन क्षेत्र के वविधिकरण को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (National Institute of Design) के साथ सहयोग कयि गया है और गांधीनगर में एक पटसन डिजाइन प्रकोष्ठ (Jute Design Cell) खोला गया है।
- राज्य सरकारों, वशिष रूप से पूरवोत्तर क्षेत्र तथा सड़क परिवहन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय जैसे वभिगों के साथ पटसन

- जयो-टेक्सटाइल्स और एगरो-टेक्सटाइल्स (Jute Geo Textiles and Agro-Textiles) के संवर्द्धन की भी शुरुआत की गई है।
- पटसन क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये सरकारी एजेंसियों द्वारा बी-ट्विल सेकिंग (B-Twill sacking)की खरीद के लिये एकीकृत प्लेटफॉर्म मुहैया कराने हेतु दिसंबर, 2016 में जूट स्मार्ट (Jute SMART)नामक एक ई-गवर्नमेंट पहल की भी शुरुआत की गई थी।
 - इसके अलावा, जेसीआई, एमएसपी और वाणज्यिकि प्रचालनों के अंतर्गत पटसन की खरीद पर पटसन किसानों को 100 प्रतिशत नधियों का अंतरण ऑनलाइन किया जा रहा है।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mandatory-jute-packaging-norms-extended>

